Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

06 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. भारत ने औषधीय पौधों के संरक्षण और खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें RET प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

4 अगस्त, 2025 को आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) ने ईश वेद-बायोप्लांट्स वेंचर के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoUs) और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

• समझौतों का उद्देश्य पूरे भारत में औषधीय पौधों के संरक्षण, प्रसार और जागरूकता को मजबूत करना है।

• केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव, जो आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) दोनों का कार्यभार संभालते हैं, की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में इन समझौता ज्ञापनों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। यह रणनीतिक सहयोग पारंपरिक पादप-आधारित उपचार को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और स्थायी प्रथाओं के साथ एकीकृत करने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है।

• NMPB ने टिशू कल्चर तकनीक का उपयोग करके दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त (RET) औषधीय पादप प्रजातियों के संरक्षण और जर्मप्लाज्म परिरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ईश वेद-बायोप्लांट्स वेंचर के साथ एक समर्पित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों को पुनर्जीवित करना है।

Key Points:-

(i) ईश वेद-बायोप्लांट्स वेंचर के साथ समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में, यह समझौता औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए टिकाऊ और स्केलेबल खेती प्रोटोकॉल विकसित करने पर भी केंद्रित है। ये प्रयास उच्च-गुणवत्ता वाले आयुष-आधारित स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने और पादप सामग्री की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(ii) AIIMS परिसर में एक राष्ट्रीय स्तर के औषधीय पादप उद्यान की स्थापना हेतु NMPB, AIIA और AIIMS-नई दिल्ली के बीच एक अलग त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस उद्यान का उद्देश्य रोगियों, चिकित्सा छात्रों और आम जनता के बीच भारत के औषधीय वनस्पतियों और उनके चिकित्सीय महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

(iii) यह उद्यान एक शैक्षिक और जागरूकता केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो चिकित्सा छात्रों, शोधकर्ताओं और अस्पताल आने वालों को औषधीय पौधों के जीवित नमूनों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य औषधीय पौधों के नैदानिक उपयोग, पारिस्थितिक महत्व और भारत की आयुष प्रणालियों में उनकी भूमिका के बारे में गहरी समझ विकसित करना है।

INTERNATIONAL

1. भारत ने एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन के लिए वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत 4 नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग किया।

अगस्त 2025 में, भारत सरकार (GoI) ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के साथ साझेदारी में, "भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल (GCBI)" के तहत, चार विकास परियोजनाओं के पहले चरण का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य नौ सहयोगी देशों को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद करना है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन विदेश मंत्रालय (MEA) के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प ने नई दिल्ली में किया।

• इन परियोजनाओं का उद्देश्य ज्ञान साझाकरण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन में वैश्विक दक्षिण के देशों का समर्थन करना है। इसमें भाग लेने वाले नौ देश नेपाल, जाम्बिया, लाओस, बेलीज़, बारबाडोस, सेंट किट्स और नेविस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो और दक्षिण सूडान हैं।

• शुरू की गई चार परियोजनाएं अलग-अलग क्षेत्रों को कवर करती हैं: चावल सुदृढ़ीकरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (नेपाल), डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्मों का विकास (जाम्बिया, लाओस), जनगणना की तैयारी में प्रशिक्षण (बेलीज, बारबाडोस, सेंट किट्स और नेविस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो), और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल (दक्षिण सूडान)।

• इन परियोजनाओं को विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) जैसे विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा समर्थित किया जाता है।

Key Points:-

(i) भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल (GCBI) को पहली बार विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सितंबर 2023 में 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान पेश किया था। यह एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन में विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित है।

(ii) यह कार्यक्रम भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है, और 400 से अधिक विशिष्ट पाठ्यक्रमों के साथ प्रतिवर्ष 12,000 प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करता है। अब तक, 160 देशों के 2.25 लाख से अधिक पेशेवर इन पहलों से लाभान्वित हो चुके हैं।

(iii) नौ साझेदार देशों के लिए चयनित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सितंबर 2025 तक शुरू होने वाले हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल भारत के संस्थानों में संबंधित देशों के नामित अधिकारियों और पेशेवरों की भागीदारी के साथ संचालित किए जाएंगे।

2. मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 107वां सदस्य बन गया।

अगस्त 2025 में, नई दिल्ली में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्रालय (MEA), भारत सरकार को अनुसमर्थन पत्र सौंपने के बाद, मोल्दोवा गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का 107वां सदस्य बन गया।

• मोल्दोवा की राजदूत एना तबान ने दिल्ली में एक आधिकारिक समारोह में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) पी.एस. गंगाधरन को अनुसमर्थन पत्र सौंपा। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग के प्रति मोल्दोवा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• मोल्दोवा के ISA में शामिल होने का प्राथमिक लक्ष्य सौर ऊर्जा का लाभ उठाकर और ISA के ऊर्जा सहयोग के वैश्विक ढांचे में भाग लेकर स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।

• मोल्दोवा ने दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में अपने दूतावास के उद्घाटन के दौरान आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और मोल्दोवा के उप-प्रधानमंत्री मिहाई पोपसोई ने हस्ताक्षर किए।

Key Points:-

(i) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) एक अंतर-सरकारी संधि-आधारित संगठन है जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत सीओपी21 में संयुक्त रूप से की थी। आईएसए वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए कार्य करता है।

(ii) ISA का लक्ष्य 2030 तक सौर परियोजनाओं के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। यह वैश्विक स्तर पर सौर परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और कार्यान्वित करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs), विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs), नागरिक समाज और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ सहयोग करता है।

(iii) मोल्दोवा के शामिल होने के साथ, ISA में अब 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हो गए हैं। यह गठबंधन 100 से ज़्यादा देशों का समर्थन करता है और सौर प्रौद्योगिकियों की लागत कम करके और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुँच में सुधार करके अल्प विकसित देशों (LDCs) और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) को सौर समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

3. भारत हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO-IRCH कार्यशाला की मेजबानी करेगा।

6 से 8 अगस्त 2025 तक, भारत नई दिल्ली/गाजियाबाद में प्रतिष्ठित WHIO-हर्बल दवाओं

के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग (IRCH) कार्यशाला की मेज़बानी करेगा। आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से आयोजित और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग (PCIM&H) द्वारा समर्थित इस वैश्विक कार्यक्रम का उद्देश्य नियामक क्षमता को मज़बूत करना और हर्बल दवाओं की सुरक्षा एवं प्रभावकारिता सुनिश्चित करना है।

• कार्यशाला का उद्घाटन आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO-IRCH) की अध्यक्ष डॉ. किम सुंगचोल द्वारा किया जाएगा। भूटान, ब्रुनेई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पैराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका, युगांडा और ज़िम्बाब्वे जैसे देशों के प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की उम्मीद है, जबकि ब्राज़ील, मिस्र और अमेरिका के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल होंगे।

• एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करते हुए, यह कार्यशाला वैश्विक सहयोग और तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी, जिसमें सुरक्षा और प्रभावकारिता तंत्र को मजबूत करना, नियामक अभिसरण को आगे बढ़ाना और दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को सशक्त बनाना शामिल है।

• विचार-विमर्श में WHO-IRCH कार्य समूह 1 और 3 की समीक्षा शामिल होगी, जो क्रमशः हर्बल दवाओं की सुरक्षा, विनियमन, प्रभावकारिता और इच्छित उपयोग पर केंद्रित होंगे। अतिरिक्त सत्रों में पूर्व-नैदानिक अनुसंधान, नियामक ढाँचों और सुरक्षा संबंधी मामलों के अध्ययनों पर चर्चा होगी, जिसमें अश्वगंधा (विथानिया सोम्नीफेरा) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Key Points:-

(i) प्रतिभागियों को PCIM&H प्रयोगशालाओं में HPTLC (उच्च-प्रदर्शन पतली परत क्रोमैटोग्राफी) का उपयोग करके हर्बल औषधि पहचान, भारी धातु विश्लेषण और कीमो-प्रोफाइलिंग तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण का उद्देश्य हर्बल औषधि में गुणवत्ता नियंत्रण और फार्माकोविजिलेंस को मज़बूत करना है।

(ii) इस कार्यक्रम में आयुष सुरक्षा (फार्माकोविजिलेंस) कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मजबूत फार्माकोविजिलेंस प्रथाओं के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा निगरानी को बढ़ाना है।

(iii) प्रतिनिधि भारत के एकीकृत स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए PCIM&H, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (NIUM) और नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) सहित प्रमुख भारतीय संस्थानों का दौरा करेंगे। इस कार्यशाला से वैश्विक मानकों के सामंजस्य और पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

BANKING & FINANCE

1. PFRDA ने डिजिटल सहभागिता बढ़ाने के लिए "PFRDA कनेक्ट" पहल के तहत आधुनिक वेबसाइट लॉन्च की।

4 अगस्त 2025 को, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने PFRDA CONNECT डिजिटल परिवर्तन पहल के तहत अपनी आधुनिक वेबसाइट आधिकारिक तौर पर लॉन्च की। इस नए प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत के पेंशन क्षेत्र में ग्राहकों, बिचौलियों और आम जनता के लिए पारदर्शिता, पहुँच और दक्षता बढ़ाना है।

• PFRDA के अध्यक्ष एस. रमन ने नई दिल्ली में नई साइट का अनावरण किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह पहल पेंशन क्षेत्र में तकनीक-संचालित, सक्रिय और पारदर्शी नियामक वातावरण को बढ़ावा देने के PFRDA के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

• वेबसाइट को भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (GIGW) और वेब सामग्री पहुंच दिशानिर्देश (WCAG) के पूर्ण अनुपालन में बनाया गया है, जिससे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सरकारी मानक डिजिटल अनुभव सुनिश्चित होता है।

• नई वेबसाइट डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफ़ोन सहित सभी उपकरणों के लिए एक उत्तरदायी इंटरफ़ेस प्रदान करती है। आसान नेविगेशन के लिए, सामग्री को नीतिगत अपडेट, परिपत्रों, पेंशन योजनाओं और अनुपालन आवश्यकताओं को शामिल करते हुए सहज ज्ञान युक्त अनुभागों में पुनर्गठित किया गया है।

Key Points:-

(i) उन्नत प्लेटफॉर्म में एक शक्तिशाली खोज इंजन, त्वरित अपडेट के लिए एक मॉड्यूलर सामग्री प्रबंधन प्रणाली (CMS) और अन्य नियामक पोर्टलों के साथ सहज एकीकरण शामिल है - जो उपयोगकर्ताओं और व्यवस्थापकों दोनों के लिए उपयोगिता में सुधार करता है।

(ii) इंटरैक्टिव टूल्स, शैक्षिक संसाधनों और डिजिटल आउटरीच सुविधाओं के साथ, इस साइट का उद्देश्य पूरे भारत में पेंशन साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत जानकारी के लिए एक केंद्रीय डिजिटल केंद्र के रूप में कार्य करता है।

(iii) वेबसाइट का शुभारंभ, पेंशन प्रशासन को डिजिटल रूप से बदलने के लिए व्यापक PFRDA CONNECT (टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर - TARCH) परियोजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत के बढ़ते उपयोगकर्ता आधार के लिए एक सुलभ, कुशल और पारदर्शी पेंशन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के PFRDA के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।

2. UPI ने 707 मिलियन दैनिक लेनदेन के साथ नया मानक स्थापित किया, जो भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2 अगस्त 2025 को, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) ने एक ही दिन में 707 मिलियन से अधिक लेनदेन करके एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की—जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। यह रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में UPI के बढ़ते प्रभुत्व को रेखांकित करती है।

• UPI ने 2 अगस्त को पहली बार 70 करोड़ दैनिक लेनदेन का आंकड़ा पार किया, जो दो साल पहले

की तुलना में दोगुना है, जब इसका औसत लेनदेन प्रतिदिन लगभग 35 करोड़ था। अगस्त 2024 तक, दैनिक लेनदेन की संख्या 50 करोड़ तक पहुँच गई थी, जिससे यह हालिया उभार तेज़ी से अपनाए जाने का स्पष्ट संकेत है।

• विशेषज्ञ इस वृद्धि का श्रेय प्रत्येक माह की शुरुआत में होने वाली नियमित वित्तीय गतिविधियों को देते हैं, जैसे कि किराया भुगतान, उपयोगिता बिल, आपातकालीन स्थानान्तरण और वेतन भुगतान - जो दैनिक वित्तीय आदतों में UPI के गहन एकीकरण को दर्शाता है।

• UPI अब भारत के लगभग 85% डिजिटल भुगतानों को संसाधित करता है और दुनिया के लगभग आधे रीयल-टाइम डिजिटल भुगतानों को संभालता है। कुल UPI ट्रैफ़िक में व्यापारी लेनदेन का योगदान लगभग 62% है, जो व्यवसाय-से-उपभोक्ता (B2C) पारिस्थितिकी तंत्र में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) जुलाई 2025 में, UPI ने ₹25.08 लाख करोड़ मूल्य के 19.47 बिलियन लेनदेन दर्ज किए, यानी औसतन 628 मिलियन दैनिक लेनदेन, जो जून के 613 मिलियन से ज़्यादा थे। यह पिछले महीने की तुलना में मात्रा में 35% की साल-दर-साल वृद्धि और 4% की मासिक वृद्धि दर्शाता है।

(ii) 2026 तक 1 बिलियन दैनिक UPI लेनदेन तक पहुंचने के सरकार के लक्ष्य के साथ, विश्लेषकों ने बताया कि विकास वक्र सही रास्ते पर है - बशर्ते कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को फिर से लागू करने जैसे नियामक कदम दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करें।

(iii) UPI की उपलब्धि डिजिटल फिनटेक इनोवेटर के रूप में भारत की भूमिका को और पुख्ता करती है। स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच और संपर्क रहित भुगतान के साथ, UPI वित्तीय समावेशन को गति देता है—खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में—और साथ ही छोटे व्यवसायों, डिजिटल विक्रेताओं और उपभोक्ता सुविधाओं का समर्थन करता है।

3. IDFC फर्स्ट बैंक और इंडिगो ने मास्टरकार्ड और रुपे के साथ नया 'इंडिगो IDFC फर्स्ट डुअल क्रेडिट कार्ड' लॉन्च किया।

अगस्त 2025 में, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने इंडिगो एयरलाइंस के साथ मिलकर 'इंडिगो आईडीएफसी फर्स्ट डुअल क्रेडिट कार्ड' नाम से एक को-ब्रांडेड डुअल नेटवर्क क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस अभिनव उत्पाद का उद्देश्य एकीकृत क्रेडिट सीमा और एकल बिलिंग संरचना के तहत दो कार्ड—मास्टरकार्ड और रुपे—की पेशकश करके यात्रा और भुगतान की सुविधा को बढ़ाना है।

• यह डुअल क्रेडिट कार्ड भारत में किसी निजी क्षेत्र के बैंक और किसी प्रमुख एयरलाइन द्वारा अपनी तरह का पहला ऑफर है। यह उपयोगकर्ताओं को मास्टरकार्ड और रुपे दोनों क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है, जिससे उन्हें एक ही क्रेडिट सीमा के साथ व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त होती है।

• ग्राहकों को दोनों कार्डों पर किए गए लेन-देन का एक ही समेकित मासिक विवरण प्राप्त होगा। इससे खर्चों पर बेहतर नज़र रखने में मदद मिलती है और

कई कार्ड बिलों के कारण होने वाली उलझन से बचा जा सकता है।

• इस कार्ड की ज्वाइनिंग और वार्षिक फीस 4,999 रुपये (GST सहित) है। दूसरे वर्ष से, वही वार्षिक शुल्क लागू होता है - जब तक कि आवेदक FD-समर्थित संस्करण का चयन नहीं करता है, जो बैंक के साथ कम से कम 1 लाख रुपये की सावधि जमा बनाए रखने पर शुल्क माफ कर देता है।"

Key Points:-

(i) एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक कार्ड के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) और अलग-अलग लेनदेन प्राथमिकताएं निर्धारित करने की क्षमता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है और उपयोगकर्ता को बेहतर नियंत्रण मिलता है।

(ii) अतिरिक्त लाभों में अधिकतम ₹1 करोड़ का हवाई दुर्घटना बीमा कवर और ₹10 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर शामिल है। यह कार्ड ₹50,000 तक का कार्ड खो जाने पर देयता कवरेज भी प्रदान करता है।

(iii) यह साझेदारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की फिनटेक-संचालित बैंकिंग सेवाओं को इंडिगो के विशाल यात्रा नेटवर्क के साथ जोड़ती है। यह मुख्य रूप से नियमित यात्रा करने वाले और डिजिटल-प्रेमी उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन की गई है जो घरेलू (RuPay) और वैश्विक (मास्टरकार्ड) लेनदेन में लचीलापन चाहते हैं।

4. जनरली ग्रुप और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 'जनरली सेंट्रल' के रूप में नई संयुक्त उद्यम ब्रांड पहचान का अनावरण किया।

अगस्त 2025 में, जेनेराली ग्रुप और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने अपने जीवन और सामान्य बीमा संयुक्त उद्यम के लिए एक नए ब्रांड की पहचान का अनावरण किया, जिसे अब 'जेनेराली सेंट्रल' के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है, जो भारत के बीमा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है।

• इस नए संयुक्त उद्यम में 'जनरली सेंट्रल' ब्रांड के तहत दो नई इकाइयाँ शामिल की गई हैं: जीवन बीमा घटक अब जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में काम करेगा, और सामान्य बीमा प्रभाग अब जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में काम करेगा। यह नाम परिवर्तन ब्रांडिंग को सुव्यवस्थित करने और उपभोक्ता पहचान बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

• इस संयुक्त उद्यम के पुनःब्रांडिंग का उद्देश्य 50 से ज़्यादा देशों में कार्यरत जेनेराली समूह की अंतर्राष्ट्रीय बीमा विशेषज्ञता को सीबीआई के 4,500 से ज़्यादा शाखाओं वाले व्यापक घरेलू नेटवर्क के साथ जोड़ना है। इस सहयोग से बीमा की पहुँच, विशेष रूप से भारत के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, बढ़ने की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) शेयरधारिता संरचना अपरिवर्तित बनी हुई है,

जिसमें जनरली ग्रुप के पास 74% हिस्सेदारी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास संयुक्त उद्यम में 26% हिस्सेदारी है।

(ii) यह दोनों संस्थाओं के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करता है तथा नेतृत्व और निवेश में निरंतरता को दर्शाता है।

(iii) रीब्रांडिंग पहल के तहत, जनरली सेंट्रल अब एक नई विज़ुअल पहचान पेश करता है, जिसमें एक अपडेटेड लोगो, टाइपोग्राफी, एक नया वेब पोर्टल और बेहतर सोशल मीडिया उपस्थिति शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य ब्रांड जागरूकता को मज़बूत करना और आधुनिक बीमा रुझानों के अनुरूप एक अधिक डिजिटल, उपभोक्ता-केंद्रित अनुभव तैयार करना है।

5. भ्रामक प्रचार और नियामक उल्लंघनों के लिए IRDAI ने पॉलिसीबाजार पर ₹5 करोड़ का जुर्माना लगाया।

4 अगस्त 2025 को, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा अधिनियम, 1938 और IRDAI (बीमा वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2017 के तहत कई उल्लंघनों के लिए पॉलिसीबाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एक बीमा वेब एग्रीगेटर के रूप में काम कर रहा था) पर ₹5 करोड़ का जुर्माना लगाया। आदेश में नियामक मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश, सलाह और चेतावनियाँ भी शामिल थीं।

• IRDAI के दूरस्थ निरीक्षण में 11 अलग-अलग उल्लंघनों का पता चला, जिनमें पक्षपातपूर्ण और भ्रामक उत्पाद प्रचार, अनधिकृत निदेशक पदों पर आसीन प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से जुड़े हितों का टकराव, बीमा कंपनियों को प्रीमियम संग्रह भेजने में देरी और शासन ढांचे में कमियां शामिल हैं।

• नियामक ने उन मामलों को चिह्नित किया जहाँ पॉलिसीबाज़ार ने वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मानदंडों या तृतीय-पक्ष सत्यापन का खुलासा किए बिना कुछ बीमा उत्पादों को "शीर्ष" या "सर्वश्रेष्ठ" के रूप में लेबल किया। प्लेटफ़ॉर्म ने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIPs) और स्वास्थ्य पॉलिसियों का एक सीमित सेट प्रदर्शित किया, जिससे पारदर्शिता के अभाव में चुनिंदा दृश्यता और उपभोक्ता की पसंद प्रभावित हुई।

Key Points:-

(i) पॉलिसीबाज़ार ने एकत्रित प्रीमियम को बीमा कंपनियों को हस्तांतरित करने में कई दिनों की देरी की थी—जो बीमा अधिनियम की धारा 64VB द्वारा निर्धारित 24 घंटे की भुगतान आवश्यकता से कहीं ज़्यादा थी। अपने स्वयं के भुगतान गेटवे के माध्यम से प्रीमियम धारण के इस दुरुपयोग ने अनुपालन संबंधी गंभीर चिंताएँ पैदा कीं।

(ii) उल्लंघनों में IRDAI की पूर्व स्वीकृति के बिना अन्य कंपनियों में निदेशक पद धारण करने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का खुलासा न करना शामिल था। चिह्नित अतिरिक्त मुद्दों में अस्पष्ट आउटसोर्सिंग व्यवस्था, अधिकृत सत्यापनकर्ताओं को नीतियों का अनुचित टैगिंग, और कॉल-रिकॉर्डिंग प्रणालियों का अभाव शामिल था।

(iii) IRDAI ने पॉलिसीबाज़ार को 45 दिनों के भीतर ₹5 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। नियामक ने औपचारिक निर्देश, सलाह और

चेतावनियाँ भी जारी की हैं, और कंपनी को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में अपील करने का विकल्प दिया है। PB फिनटेक (पॉलिसीबाज़ार की मूल कंपनी) ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है और कहा है कि एक "कार्रवाई रिपोर्ट" उसके बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

ECONOMY & BUSINESS

1. JSW स्टील और जापान की JFE स्टील ने अनाज-उन्मुख विद्युत स्टील क्षमता का विस्तार करने के लिए 5,845 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी।

अगस्त 2025 में, भारत की जेएसडब्ल्यू स्टील और जापान की जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन ने संयुक्त रूप से अपने संयुक्त उद्यम - JSW JFE इलेक्ट्रिकल स्टील - के माध्यम से दो भारतीय संयंत्रों में कोल्ड-रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (CR-GOES) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5,845 करोड़ रुपये के विस्तार पैकेज को मंजूरी दी।

• नासिक संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता ₹4,300 करोड़ के निवेश से पाँच गुना बढ़कर 50,000 टन प्रति वर्ष (TPA) हो जाएगी। कर्नाटक के विजयनगर संयंत्र की क्षमता ₹1,545 करोड़ के अतिरिक्त निवेश से 62,000 टन प्रति वर्ष से बढ़कर 1,00,000 टन प्रति वर्ष हो जाएगी।

• ₹5,845 करोड़ (लगभग US$669 मिलियन) के कुल निवेश में ₹1,966 करोड़ की इक्विटी शामिल है, जो JSW स्टील और JFE स्टील द्वारा समान रूप से वित्तपोषित है। शेष राशि ऋण और आंतरिक निधियों के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

• पूरा होने पर, संयुक्त उद्यम 350,000 TPA की संयुक्त कोल्ड-रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील क्षमता प्रदान करेगा, जिसमें बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2028 से चरणबद्ध कमीशनिंग की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) CR-GOES एक उच्च-दक्षता वाला स्टील है जिसका उपयोग ट्रांसफार्मर, जनरेटर और इलेक्ट्रिक वाहन मोटरों में किया जाता है। यह विस्तार भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों, आयात प्रतिस्थापन रणनीति और बिजली एवं डेटा सेंटर क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायक होगा।

(ii) JSW JFE इलेक्ट्रिकल स्टील एक 50:50 संयुक्त उद्यम है जिसकी स्थापना 2023 में JSW द्वारा नासिक संयंत्र (पूर्व में थिसेनक्रुप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया) के अधिग्रहण के बाद हुई थी। यह भारत के विशिष्ट इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए JFE की उन्नत CRGO तकनीक को JSW के घरेलू पैमाने के साथ जोड़ता है।

MOUs and Agreement

1. भारत और फिलीपींस ने नौ रणनीतिक सहमति पत्रों (MoU) के साथ संबंधों को मजबूत किया।

अगस्त 2025 में, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर की नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के दौरान, भारत और फिलीपींस ने नौ समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर करके अपने उन्नत राजनयिक संबंधों को औपचारिक रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए ये समझौते द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में आधिकारिक रूप से उन्नत करने और विविध क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने का प्रतीक हैं।

- **आदान-प्रदान किए गए समझौतों में रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर एक घोषणा और भारत-फिलीपींस सहयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना (2025-2029) शामिल थी, जिसमें भविष्य के जुड़ाव के लिए एक संरचित रोडमैप तैयार किया गया था।**

- **वायु सेना वार्ता, थलसेना वार्ता और नौसेना वार्ता के लिए हस्ताक्षरित संदर्भ शर्तों के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा मिला, जिससे उच्च स्तरीय सैन्य परामर्श को और अधिक गहन बनाया गया।**

- **आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर संधि के माध्यम से न्याय और कानूनी सहयोग को मजबूत किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच न्यायिक संबंध बढ़े।**

Key Points:-

(i) दोनों देशों ने उभरते और उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में भी सहयोग किया, जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यटन और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, जिसमें इसरो और फिलीपीन अंतरिक्ष एजेंसी के बीच आशय पत्र भी शामिल है।

(ii) सांस्कृतिक कूटनीति और समुद्री सहयोग पर तट रक्षकों के बीच समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के साथ-साथ पर्यटन संबंधों को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. इंडसइंड बैंक ने राजीव आनंद को 3 साल के कार्यकाल के लिए MD और CEO नियुक्त किया है, जो 25 अगस्त, 2025 से सुमंत कठपालिया का स्थान लेंगे।

अगस्त 2025 में, इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अनुमोदन के बाद, 25 अगस्त 2025 से शुरू होने वाले तीन साल के कार्यकाल के लिए राजीव आनंद को नए प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में आधिकारिक तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की।

- **राजीव आनंद, सुमंत कठपालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 1 मई 2025 को MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया था। आनंद इससे पहले एक्सिस बैंक में उप प्रबंध**

निदेशक (DMD) के पद पर कार्यरत थे, और 2021 से 3 अगस्त 2025 तक इस पद पर रहे।

• वर्तमान में, बैंक का प्रबंधन इसकी कार्यकारी समिति (EXCO) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता बैंकिंग के प्रमुख सौमित्र सेन और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (CAO) अनिल राव शामिल हैं, जब तक कि राजीव आनंद आधिकारिक रूप से कार्यभार नहीं संभाल लेते।

• राजीव आनंद बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, उन्होंने 2009 में एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में संस्थापक एमडी और CEO के रूप में शामिल होकर अपनी उल्लेखनीय नेतृत्व यात्रा शुरू की। बाद में, उन्होंने 2013 में एक्सिस बैंक में रिटेल बैंकिंग के अध्यक्ष का पदभार संभाला और पाँच वर्षों तक इस विभाग का नेतृत्व किया, और रिटेल बैंकिंग नवाचार और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

Key Points:-

(i) 2018 से, राजीव आनंद ने एक्सिस बैंक में थोक बैंकिंग का नेतृत्व किया, जिसमें सतत विकास और संस्थागत ऋण पर विशेष ध्यान दिया गया। उनकी रणनीतिक दृष्टि ने दीर्घकालिक कॉर्पोरेट साझेदारियों को भी आकार दिया।

(ii) कॉर्पोरेट नेतृत्व के अलावा, राजीव आनंद राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रभावशाली भूमिकाएँ निभाते हैं। वे CII (भारतीय उद्योग परिसंघ) की राष्ट्रीय बैंकिंग समिति के सदस्य हैं और बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BCCI) में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

(iii) वे एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और BCCI के बोर्ड में भी हैं, जो बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में उनके नेतृत्व को उजागर करता है।

INDEX

1. नीति आयोग ने EV संक्रमण में राज्य की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 लॉन्च किया।

पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग ने अगस्त 2025 में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2024 लॉन्च किया। यह सूचकांक व्यापक स्वच्छ गतिशीलता एजेंडे के तहत अपने EV अपनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने और निगरानी करने के लिए विकसित अपनी तरह का पहला उपकरण है।

• भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) को आधिकारिक तौर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा द्वारा जारी किया गया, इस अवसर पर बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम (CEO, नीति आयोग), कामरान रिज़वी (सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय - MHI), पी.ओ. अग्रवाल (प्रतिष्ठित फेलो, नीति आयोग), और शुभेंदु सिन्हा (कार्यक्रम निदेशक - ई-मोबिलिटी, नीति आयोग) मौजूद थे, जिसमें देश भर में EV प्रगति को बढ़ावा देने के लिए उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

• IEMI 2024 सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 2 विषयगत क्षेत्रों में 16 मुख्य संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करता है और उन्हें 1000 के

पैमाने पर स्कोर देता है। स्कोरिंग प्रणाली राज्यों को तीन श्रेणियों में रखती है: फ्रंटरनर (65-99), परफॉर्मर (50-64), और एस्पिरेंट्स (0-49) उनके EV पारिस्थितिकी तंत्र की तत्परता और नीति निष्पादन के आधार पर।

• 'फ्रंटरनर्स' श्रेणी (स्कोर: 65-99) में दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ शामिल हैं, जिन्होंने EV बुनियादी ढांचे, पारिस्थितिकी तंत्र और नीति कार्यान्वयन में उन्नत तत्परता का प्रदर्शन किया है।

Key Points:-

(i) 'प्रदर्शनकर्ता' श्रेणी (स्कोर: 50-64) में कर्नाटक, तमिलनाडु (TN) और हरियाणा शामिल हैं, जो बुनियादी ढांचे और अपनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकास में लगातार प्रगति कर रहे हैं।

(ii) 'आकांक्षी' श्रेणी (स्कोर: 0-49) में ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (UP), लद्दाख और आंध्र प्रदेश (AP) शामिल हैं, जो कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं और उन्हें अपने ईवी पहलों को बढ़ाने के लिए अधिक निवेश और रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

(iii) IEMI का उद्देश्य नीति निर्माताओं, निवेशकों और हितधारकों को राज्य स्तरीय ईवी पारिस्थितिकी प्रणालियों में ताकत और अंतराल की पहचान करने में मदद करने के लिए एक गतिशील बेंचमार्किंग ढांचा प्रदान करना है, जिससे लक्षित सुधार और नीतिगत सुधार संभव हो सकें।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. ध्रुव स्पेस अगस्त 2025 में LEAP-1 मिशन के तहत स्पेसएक्स फाल्कन 9 पर पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च करेगा।

4 अगस्त, 2025 को, हैदराबाद स्थित ध्रुव स्पेस, स्पेसएक्स (स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन) के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके, अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन, LEAP-1 (लॉन्चिंग एक्सपीडिशन्स फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स-1) लॉन्च करेगा। यह मिशन दो अंतरराष्ट्रीय पेलोड—नेक्सस-01 और OTR-2 (ऑर्बिटल टेस्ट रिंग-2)—ले जाएगा और भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा।

• ध्रुव स्पेस का LEAP-1 मिशन फाल्कन 9 रॉकेट पर अंतर्राष्ट्रीय पेलोड ले जाने के लिए P-30 (प्लेटफॉर्म-30) उपग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा।

• यह प्लेटफॉर्म, जो पहले जनवरी 2025 में ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के PSLV-C58 (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान-C58) मिशन पर उड़ान भर चुका है, 10-15 किलोग्राम के पेलोड को समायोजित कर सकता है और विविध रिमोट सेंसिंग और पृथ्वी अवलोकन कार्यों का समर्थन करता है।

• इस मिशन में दो विदेशी पेलोड शामिल हैं: अकुला टेक का नेक्सस-01 और एस्पर सैटेलाइट्स का ओटीआर-2। नेक्सस-01 अग्नि का पता लगाने, विसंगतियों का पता लगाने और वर्णक्रमीय विश्लेषण के लिए एक उन्नत ऑन-ऑर्बिट AI/ML (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) आधारित पेलोड है। OTR-2, एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर, विस्तृत

वर्णक्रमीय इमेजिंग प्रदान करने की अपनी क्षमता का उपयोग करके उच्च-रिज़ॉल्यूशन पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान करेगा।

Key Points:-

(i) मिशन का संचालन और डेटा प्रबंधन ध्रुव स्पेस के ISOCS (एकीकृत अंतरिक्ष संचालन और कमांड सूट) के माध्यम से किया जाएगा। GSaaS (ग्राउंड स्टेशन-एज़-ए-सर्विस) प्लेटफ़ॉर्म वास्तविक समय पेलोड नियंत्रण, अपलिंक और डाउनलिंक मिशन संचालन का समर्थन करेगा ताकि प्रक्षेपण से लेकर डेटा संग्रह तक सुचारू समन्वय सुनिश्चित हो सके।

(ii) LEAP-1 मिशन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। इसे उपग्रह सेवाओं तक वैश्विक पहुँच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित उपग्रह कार्यों और सुदूर संवेदन अनुप्रयोगों में ध्रुव स्पेस की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा।

(iii) इस मिशन का अर्थ है वैश्विक निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की बढ़ती भूमिका। ध्रुव स्पेस, इस व्यावसायिक शुरुआत के माध्यम से, छोटे पेलोड प्रक्षेपणों का समर्थन करने और उद्योगों, शिक्षा जगत और सरकारी अनुसंधान एजेंसियों के लिए उपग्रह पहुँच का विस्तार करने के लिए स्केलेबल बुनियादी ढाँचा और उपग्रह प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करेगा।

2. ISRO ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख में HOPE मिशन लॉन्च किया

31 जुलाई 2025 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लद्दाख की त्सो कार घाटी में, जो मंगल और चंद्रमा जैसे उच्च-ऊंचाई वाले रेगिस्तानी वातावरण में स्थित है, HOPE (ग्रह अन्वेषण के लिए हिमालयन आउटपोस्ट) एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया। 1 से 10 अगस्त 2025 तक चलने वाला यह मिशन, भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान के लिए इसरो की तैयारियों के एक हिस्से के रूप में, चरम स्थितियों में चालक दल की तैयारी और अंतरिक्ष उड़ान प्रणालियों का परीक्षण करेगा।

- **HOPE मिशन लद्दाख में 4,530 मीटर की ऊँचाई पर स्थित त्सो कार घाटी में संचालित किया जा रहा है। मंगल ग्रह के भूभाग से इसकी समानता के कारण इसे चुना गया है—जो उच्च पराबैंगनी विकिरण, निम्न वायुमंडलीय दबाव, अत्यधिक ठंड और खारे पर्माफ्रॉस्ट की विशेषता रखता है—यह मानव अंतरिक्ष उड़ान सिमुलेशन के लिए एक आदर्श परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है।**

- **मंगल ग्रह जैसे आवास सिमुलेशन के रूप में डिज़ाइन किए गए, HOPE का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का गहन परीक्षण करना है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO), चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव मिशनों के लिए ISRO के व्यापक रोडमैप का समर्थन करता है।**

• मिशन एक सघन आवास परत का उपयोग करता है जिसमें 8 मीटर व्यास वाला एक क्रू मॉड्यूल और 5 मीटर का एक उपयोगिता मॉड्यूल शामिल है, दोनों ही अलौकिक सतहों पर वास्तविक जीवन के वर्कफ़्लो का अनुकरण करने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष में जीवन का अनुकरण करने के लिए दो क्रू सदस्य इस आवास के अंदर 10 दिनों तक एकांत में रहेंगे।

Key Points:-

(i) HOPE जैव-चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक निगरानी, सतही परिचालन प्रोटोकॉल, सूक्ष्मजीवी नमूनाकरण, दैनिक लय विश्लेषण और स्वास्थ्य-निगरानी मूल्यांकन सहित कई अध्ययन करेगा। इसमें भाग लेने वाले संस्थानों में IIST (त्रिवेंद्रम), RGCB (त्रिवेंद्रम), IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे और इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन, बेंगलुरु शामिल हैं।

(ii) यह उच्च-निष्ठा सिमुलेशन एक महत्वपूर्ण "भविष्य के लिए पूर्वाभ्यास" के रूप में कार्य करता है, जो भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं के साथ पूरी तरह से संरेखित है, जिसमें गगनयान, एक नियोजित चालक दल कक्षीय मिशन और 2040 तक चालक दल के साथ चंद्र लैंडिंग जैसे अगली पीढ़ी के लक्ष्य शामिल हैं। निष्कर्ष सीधे अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, मिशन प्रोटोकॉल और जीवन-समर्थन प्रणाली डिजाइन को सूचित करेंगे।

(iii) HOPE, ISRO के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC) और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग के एक नए युग का प्रतीक है, जिसमें प्रोटोप्लेनेट आवास विकसित कर रहा है। यह मिशन नवंबर 2024 में लद्दाख मानव एनालॉग मिशन (LHAM) और जुलाई 2025 में अलगाव अध्ययन 'अनुगामी' जैसे पूर्व एनालॉग अभ्यासों पर आधारित है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के नेतृत्व को और मज़बूत करता है।

OBITUARY

1. जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

5 अगस्त 2025 को, जम्मू और कश्मीर (J&K) के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश (UP) के बागपत जिले के हिसावदा गाँव में जन्मे, वे एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई उच्च-स्तरीय राज्यपाल और संसदीय भूमिकाएँ निभाईं।

• सत्य पाल मलिक ने अपना संसदीय जीवन उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में संसद सदस्य (MP) के रूप में शुरू किया, जो 1980 से 1989 के बीच सेवारत रहे। बाद में उन्होंने 1989 से 1991 तक लोकसभा सांसद के रूप में अलीगढ़, यूपी का प्रतिनिधित्व किया। उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन ने उन्हें मजबूत जमीनी स्तर के संबंधों और राष्ट्रीय राजनीति में गहरी भागीदारी वाले नेता के रूप में चिह्नित किया।

• अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पाँच भारतीय राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मलिक को 2017 में बिहार का 27वाँ राज्यपाल नियुक्त किया गया और 2018 में, उन्होंने कुछ समय के लिए ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। उनका सबसे उल्लेखनीय कार्यभार 2018 से 2019 तक, राजनीतिक रूप से संवेदनशील

अवधि के दौरान, जम्मू और कश्मीर के 10वें राज्यपाल के रूप में रहा।

Key Points:-

(i) 2019 से 2020 तक, उन्होंने गोवा के 18वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने अपनी प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ जारी रखीं। इसके बाद, उन्हें मेघालय का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया, और यह पद उन्होंने 2020 से 2022 तक संभाला। इन नियुक्तियों ने भारत भर में विविध क्षेत्रीय शासन चुनौतियों से निपटने में उनकी अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित किया।

(ii) 1990 में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में सत्यपाल मलिक को केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। उनकी कुशाग्रता तब और निखर कर सामने आई जब 2012 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रशासनिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और 2014 में उन्हें इसी पद पर पुनः नियुक्त किया गया।

(iii) मलिक के करियर का एक महत्वपूर्ण क्षण 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य के पुनर्गठन से पहले जम्मू-कश्मीर के अंतिम राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल था। इस परिवर्तन के बाद, राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया गया और जी.सी. मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने। यह अवधि जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

Static GK

National Medicinal Plants Board (NMPB)	CEO : डॉ. महेश कुमार दाधीच	मुख्यालय: नई दिल्ली
Ministry of External Affairs of India(MEA)	केंद्रीय मंत्री: एस. जयशंकर	मुख्यालय: नई दिल्ली
NITI Aayog	CEO : श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम	मुख्यालय: नई दिल्ली
Moldova	राजधानी: चिसीनाउ	अध्यक्ष: मैया सैंडू
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)	अध्यक्ष : शिवसुब्रमण्यम रमन	मुख्यालय: नई दिल्ली
IDFC FIRST Bank Ltd.	MD & CEO : वी. वैद्यनाथन	मुख्यालय: मुंबई
Central Bank of India	CEO : मतम वेंकट राव	मुख्यालय: मुंबई
IndusInd Bank Limited	स्थापना: 1994	मुख्यालय: मुंबई
Philippines	मुद्रा: फिलीपीन पेसो	राष्ट्रपति: बोंगबोंग मार्कोस
Dhruva Space	CEO : संजय श्रीकांत नेक्कंती	मुख्यालय : हैदराबाद, तेलंगाना
ISRO	अध्यक्ष: वी. नारायणन	मुख्यालय: बेंगलुरु
World Health Organization (WHO)	उप महाप्रबंधक: माइकल रयान	मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड